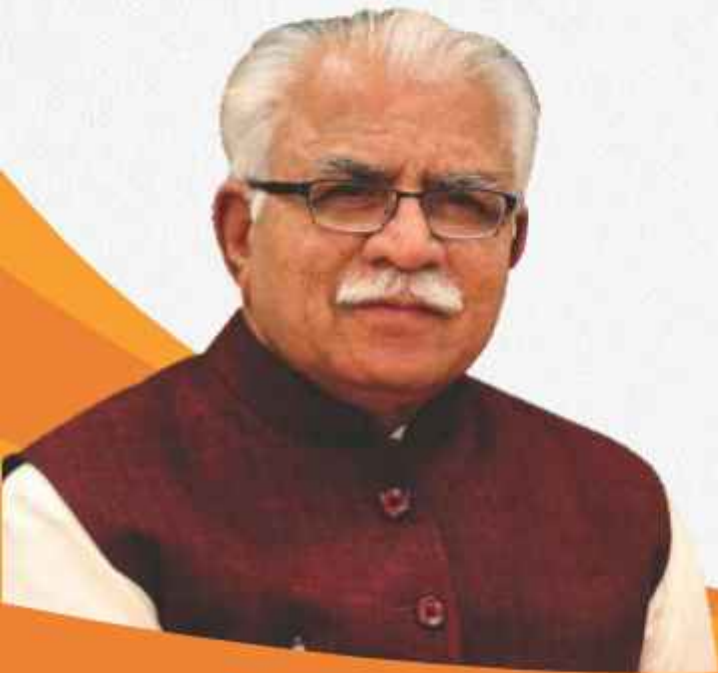


75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 05.02.2024 से 10.02.2024)



भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करना

(दिनांक 05.02.2024)

प्रभाव : पुलिस की कार्यप्रणाली और आचरण के विरुद्ध जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों के समाधान हेतु राज्यों में गठित पुलिस शिकायत प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने के उद्देश्य से आज हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा सभी राज्यों की पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन

देश में पहली बार आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने सत्ता में आने के बाद पुलिस शिकायत प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए। हमारा ध्येय यही था कि जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए न्यायपूर्ण रास्ता



साप्ताहिक सूचना पत्र



अपनाया जाए। पहले दिन से ही हमारा लक्ष्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है और इसके लिए कई कारगर कदम भी उठाए गए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के अनेक काम करते हुए हम सिस्टम में पारदर्शिता लेकर आए हैं।

पुलिस की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए और वित्तीय मामलों से निपटने हेतु हरियाणा राज्य एनफोर्समेंट ब्यूरो का गठन किया है, जिसके तहत कर चोरी, बिजली चोरी, खनन चोरी या नहर पानी की चोरी इत्यादि गतिविधियों पर लगाम लगाई जा रही है। राज्य सरकार ने 33 महिला थाने स्थापित किए हैं और पुलिस में भी महिलाओं की संख्या

बढ़ाई है। साथ ही, साइबर क्राइम से निपटने के लिए अलग से साइबर थाने बनाये हैं और हर पुलिस थानों में साइबर डेस्क की स्थापना की है।

जनता के मन में यह शंका होती थी कि पुलिस द्वारा उनके साथ किये जाने वाले गलत व्यवहार की शिकायत वे कहां दर्ज करवाएं, जहां उन्हें न्याय मिले। इसी अवधारणा के साथ राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण अस्तित्व में आया। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण में लगभग 2 हजार शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने संबंधित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया है व जुर्माना



साप्ताहिक सूचना पत्र

भी लगाया है। इसलिए आज जनता में प्राधिकरण के प्रति विश्वास बढ़ा है कि उनकी शिकायतों की सुनवाई हो रही है।

माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ, भविष्य की जरूरतों के अनुरूप प्रशासनिक सेवा को तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। राज्य में लगभग साढ़े 3 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस प्रकार जनता की

अपेक्षाओं पर खरा उतर सकें। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवा भाव से काम करने की जरूरत है।

इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन एक अच्छा निर्णय है, ताकि सभी राज्य अपनी-अपनी बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान करें। उन्होंने सम्मेलन के मुख्य वक्ता श्री प्रकाश सिंह, पूर्व डीजीपी (सेवानिवृत्त) का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि श्री प्रकाश सिंह ने हमेशा ही पुलिस में सुधार लाने पर जोर दिया है और इसके लिए वे अथक प्रयास कर रहे हैं।



साप्ताहिक सूचना पत्र

एचईआरसी के नवनियुक्त अध्यक्ष नन्द लाल शर्मा ने की शिष्टाचार भेंट

(दिनांक 05.02.2024)

प्रभाव : हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री नन्द लाल शर्मा जी ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर कैसे हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को और अधिक बेहतर सेवा दे सकते हैं, उनकी बेहतरी के लिए और क्या कर सकते हैं तथा ग्रीन एनर्जी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कैसे व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है, इन सब विषयों पर चर्चा हुई।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है कि 2030 तक हर हालत में देश में 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का निर्माण करना है। उस दौरान जो भारत की बिजली आवश्यकता होगी उसका 50 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी यानी

नॉन फॉसिल फ्यूल (गैर जीवाश्म ईंधन) से पूरी की जाएगी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हर राज्य को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, इस दिशा में हरियाणा अपना कैसे सहयोग दे सकता है, उसको लेकर यह विचार विमर्श हुआ।



साप्ताहिक सूचना पत्र

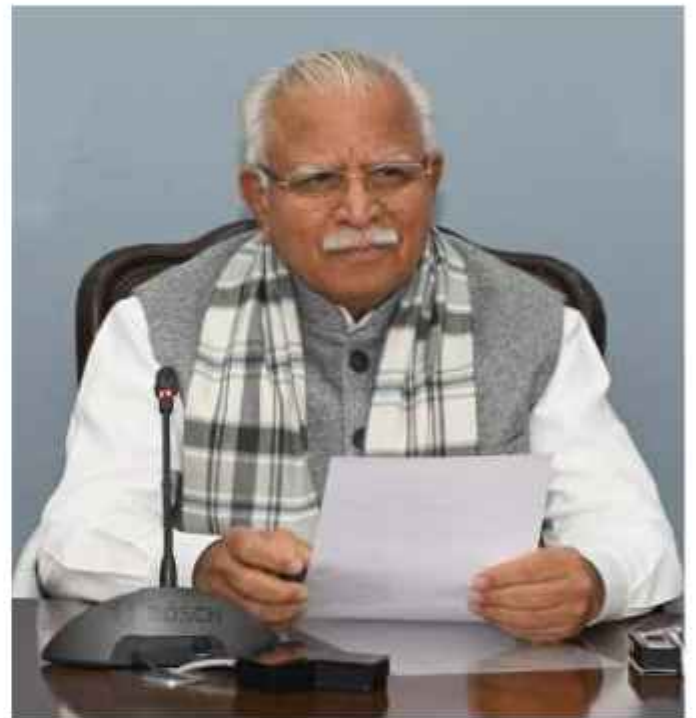
पानीपत जिले की 9 ओडीआर सड़कों के सुधार को मंजूरी प्रदान

(दिनांक 05.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने पानीपत जिले में 9 ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर 19 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आएगी।

बाजार केंद्रों, तहसील मुख्यालयों, ब्लॉक विकास मुख्यालयों, रेलवे स्टेशनों आदि तक पहुंच प्रदान करने वाली सड़कों को अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) के रूप में जाना जाता है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन परियोजनाओं में गांव बिंझौल से गांव भादर तक 5.10 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण शामिल है, इसी प्रकार, गांव जट्टल से खुखराना तक, गांव शोंधापुर से बिंझौल तक, गांव सिवाह से डाडोला तक, तथा



पानीपत रोड से काबरी, सिठाना होते हुए एलओसीएल रिफाइनरी तक सुदृढ़ीकरण शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि यह पहल हरियाणा सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और निस्संदेह राज्य भर में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार करके जनता को पर्याप्त लाभ पहुंचाएगी।



साप्ताहिक सूचना पत्र

हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी (एचपीजीसीएल) की बैठक

(दिनांक 06.02.2024)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल देर सायं हुई हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी (एच-पीजीसीएल) की बैठक में 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता का नये लगाने वाले दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर को बनाने के लिए टेंडर का कार्य भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को 6900 करोड़ रुपये में देने की अनुमति प्रदान की गई। बीएचईएल इस कार्य को 57 महीने की समयावधि में पूरा करेगी।

इस प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी जबकि अभी तक सब-क्रिटिकल यूनिट लगे हुए हैं। यह पहले लगे यूनिट से 8 प्रतिशत ज्यादा क्षमता के हैं। इसमें कोयले की खपत कम होगी और बिजली सस्ती बनेगी।

इस परियोजना से हरियाणा के नागरिकों के लिए निर्बाध बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सभी उपकरण लगाने का प्रावधान किया गया है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

पंचकूला में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत नैतिकता शिविर (एथिक्स कॉन्कलेव) का आयोजन होना

(दिनांक 06.02.2024)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज पंचकूला में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आयोजित नैतिकता शिविर (एथिक्स कॉन्कलेव) में उपस्थित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि भौतिक निर्माण से पहले व्यक्तित्व निर्माण आवश्यक है। एक बार व्यक्तित्व का निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण अपने आप हो जाएगा। व्यक्तित्व निर्माण पर

सरकारों का ध्यान जाएगा पहले किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुशासन में नैतिकता के भाव को आत्मसात करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की है। अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास बढे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों में संकल्प, ताकत व मनोबल के साथ समाज सेवा के भाव को जागृत



साप्ताहिक सूचना पत्र

करने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली तब शासन और अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यप्रणाली बदलाव की आवश्यकता को देखते हुए 25 दिसंबर 2015 को प्रथम सुशासन दिवस पर व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अनेक पहल की शुरुआत की। पिछले लगभग साढ़े 9 सालों में हमने सुशासन की दिशा में अनेक सफल कार्य किए हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा एक—हरियाणवी एक की भावना से प्रदेश का समान विकास सुनिश्चित किया। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने सात 'एस'— शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन व सेवा के लक्ष्य पर कार्य करते हुए प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाया है। सभी अधिकारी इन सात 'एस'को साकार करने की दिशा में कार्य करेंगे तो



साप्ताहिक सूचना पत्र

समाज सुखी होगा। उन्होंने कहा कि हमने तीन 'सी- क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म करने के सफल प्रयास किए हैं।

उन्होंने कहा कि आज 2 लाख से अधिक कर्मचारी व अधिकारी का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 31 मार्च 2024 तक साढ़े 3 लाख कर्मचारी कर्मयोगी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिपा की महानिदेशक श्रीमति चंद्रलेखा बैनर्जी से आग्रह किया कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत कर्मचारियों व अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण मॉड्यूल को हिपा के पाठयक्रम में उपयोग किया जाना चाहिए। यह विशेष अभियान 15 फरवरी से 29 फरवरी तक चलाया जाएगा।

नैतिकता शिविर (एथिक्स कॉन्कलेव) को संबोधित करने उपरान्त पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि से हुए फसलों के



नुक्सान की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन चार दिनों में हरियाणा भर में वर्षा और ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों का नुकसान हुआ है। आज ही हमने ऐसे स्थानों पर स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए हैं। जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उनकी स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।



साप्ताहिक सूचना पत्र

जन संवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक

(दिनांक 06.02.2024)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां जन संवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान फील्ड से लोगों द्वारा लिखित में दी गई शिकायतों का पंजीकरण जन संवाद पोर्टल पर करें और श्रेणीवार इनका शीघ्र समाधान करें। बैठक में

विकास एवं पंचायत तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि विकास एवं पंचायत विभाग से सम्बन्धित अधिकतर मामले इंजीनियरिंग वर्कस से जुड़े हैं, इसलिए अनुमान तैयार करने के लिए राजकीय विश्वविद्यालयों व बहुतकनीकी संस्थानों में सिविल इंजीनियर कर रहे अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को कनिष्ठ अभियंताओं



साप्ताहिक सूचना पत्र

के साथ जोड़ा जाए, ताकि कनिष्ठ अभियंताओं को अनुमान तैयार करने में सहयोग मिल सके। बैठक में जानकारी दी गई कि शीघ्र ही इंजीनियरिंग कार्य से जुड़े विभागों के कनिष्ठ अभियंताओं की सूची विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी जाएगी और तीन दिन में विद्यार्थी कनिष्ठ अभियंता के साथ काम करने के लिए विकल्प दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कार्यों की मैपिंग कर श्रेणीवार सूची बनाई जाए। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि विकास एवं पंचायत विभाग से

23,364 विकास कार्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से 2370 तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग से 1281 विकास कार्य सूचीबद्ध हैं। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान शिकायतों के निपटान के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह, बिजली निगमों के चेयरमैन श्री पीके दास, सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टीसी गुप्ता तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के सहलाहकार (सिंचाई) श्री देवेन्द्र सिंह जी को विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

राज्य में स्थापित की जाने वाली नई गौशालाओं के संबंध में बैठक की अध्यक्षता

(दिनांक 07.02.2024)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां राज्य में स्थापित की जाने वाली नई गौशालाओं के संबंध में आयोजित की गई एक बैठक की अध्यक्षता कर प्रदेश को बेसहारा गोवंश से मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 15 फरवरी से 29 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर लगभग 60 हजार बेसहारा गोवंशों को

नजदीक की गौशालाओं में पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य की सड़कों से बेसहारा गोवंश को गौशालाओं में पहुंचाना और सड़क दुर्घटनाओं से निजात दिलाना है। इस बैठक में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जे.पी. दलाल भी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों व गौसेवा आयोग के पदाधिकारियों को



साप्ताहिक सूचना पत्र

निर्देश देते हुए कहा कि जिन पंचायतों द्वारा गौशाला स्थापित करने के प्रस्ताव आए हैं, उन पर आगामी कार्यवाही की जाए। इस अभियान के अंतर्गत बेसहारा गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाने के कार्य को तेजी से किया जाए ताकि राज्य में गौवंश की सुरक्षा की जा सकें।

इसी प्रकार, उन्होंने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे गांवों में गौचराण की भूमि चिन्हित करें और जिन गांवों में 10 एकड़ से अधिक की गौचराण की भूमि चिन्हित की जाती है तो उन गांव की पंचायतों से गौशाला स्थापित करने के लिए बातचीत की जाए।

इस संबंध में एक कमेटी का भी गठन किया जाए जिसमें गौसेवा आयोग, विकास एवं पंचायत विभाग अन्य हितधारक विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाए। उन्होंने गौसेवा आयोग के



पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि गौशालाओं की क्षमता के अनुसार ही गौवंश रखे जाए।

इसके अलावा, समय-समय पर गौशालाओं का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि गौवंश को गौशालाओं में सही प्रकार से रखा जाये। बैठक में गौसेवा आयोग के चेयरमैन श्री श्रवण कुमार गर्ग ने माननीय मुख्यमंत्री तथा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जे.पी. दलाल को अवगत कराया कि पूरे प्रदेश में 10 जनवरी, 2024 से अब तक 8200 बेसहारा गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाया गया है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक की अध्यक्षता

(दिनांक 07.02.2024)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को शीघ्र अति शीघ्र ई-भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से 5 हजार एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए हैं, ताकि संस्थागत ढंग से सेक्टर विकसित किये जा सकें। सरकार के इस कदम से अवैध कॉलोनियों के पनपने पर रोक लगेगी।

उन्होंने कहा कि प्राधिकरण अपनी सभी संपत्तियों की चाहे वह आवासीय या वाणिज्यिक या संस्थागत हो, सभी को सूचीबद्ध करे। उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड में संपदा अधिकारियों के पास नागरिकों द्वारा जमीन से संबंधित दिए गए किसी भी प्रकार के आवेदनों की जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य तौर पर दी जाए। बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) से जुड़े बीमाकृतों तथा उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा



साप्ताहिक सूचना पत्र



सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न जिलों में ईएसआई डिस्पेंसरियों के निर्माण हेतु जमीन आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में जानकारी दी गई कि जिला अंबाला में मुलाना, जिला गुरुग्राम में फरुखनगर, जिला झज्जर में दादरी तोय व झाड़ली, जिला करनाल में तरावड़ी व घरौंडा, जिला रेवाड़ी में कोसली, जिला यमुनानगर में छछरौली तथा चरखी दादरी और बरसात रोड पानीपत में ईएसआई डिस्पेंसरियां स्थापित की जाएंगी।

साथ ही हिसार में लगभग 100 बैड की सुविधाओं वाला ईएसआई अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसके लिए पहले ही जमीन आवंटित की जा चुकी है।

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी विभागों को कम कीमतों पर जमीन आवंटित करने के लिए बनाई गई नीति को मंजूरी प्रदान की गई।

इस नीति के तहत अब जनहित में विकास कार्यों हेतु एचएसवीपी द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को 50 प्रतिशत दर पर जमीन आवंटित की जाएगी। हालांकि, यह नियम केवल विभागों पर ही लागू होगा।

बोर्ड व निगमों को निर्धारित दरों पर ही जमीन का आवंटन किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विंग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा आधार पर उनके आश्रितों को नौकरी दी गई।



साप्ताहिक सूचना पत्र

84.23 करोड़ रुपये अधिक लागत से 5 एमडीआर सड़कों के सुधार को मंजूरी प्रदान

(दिनांक 07.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जिलों नामतरु भिवानी, फतेहाबाद, करनाल और झज्जर में 5 एमडीआर (प्रमुख जिला सड़कें) की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।

इस प्रोजेक्ट पर 84.23 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आएगी।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के तहत 12.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जिला भिवानी के गांव झुंपा कलां, बेहल, कैरु और भिवानी-लोहारु सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण, फतेहाबाद जिले में 11.18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भद्व-लुदेसर-जमाल से राज्य सीमा तक सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण, 24.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से करनाल जिले



के गांव कोहंड-मुनक-सलवान-असंध तक सड़कों का सुदृढीकरण, 16.74 करोड़ रुपये अनुमानित लागत से करनाल मुनक रोड का सुदृढीकरण और 19.03 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर झज्जर जिले में बहादुरगढ़ से छारा रोड तक सड़कों का सुधार शामिल है।

उन्होंने कहा कि ये पहल हरियाणा सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और निस्संदेह राज्य भर में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार करके जनता को पर्याप्त लाभ पहुंचाएगी।



साप्ताहिक सूचना पत्र

अटल भूजल योजना की राष्ट्र स्तरीय समीक्षा बैठक

(दिनांक 07.02.2024)



प्रभाव : जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की विशेष सचिव, सुश्री देबाश्री मुखर्जी आज वर्चुअल माध्यम से अटल भूजल योजना की राष्ट्र स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर कहा की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण और जल संचयन की दिशा में उठाए जा रहे सकारात्मक कदमों की आज एक बार पुनः राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। उन्होंने अटल भूजल योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा किए गए प्रयासों को सराहनीय बताया। हरियाणा

की ओर से डॉ० सतबीर सिंह कादियान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बैठक में भाग लिया। डॉ० कादियान ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा के निर्देशानुसार राज्य में पानी बचाने की दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अटल भूजल योजना के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने हरियाणा में तीव्रता से गिरते भूजल स्तर, अतिदोहित



साप्ताहिक सूचना पत्र

एवं जल संकटग्रस्त क्षेत्र में सभी गतिविधियों को क्रियान्वित किये जाने की रणनीति का विवरण प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि गिरते हुए भूजल स्तर को रोकने एवं भूजल स्तर को ऊपर उठाने हेतु हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में विभिन्न विभागों की तमाम योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर धरातल पर उतारा जा रहा है। डॉ कादियान ने बताया कि राज्य में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 36285 हेक्टेयर तथा मिकाडा द्वारा 50526 हेक्टेयर में वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिस का कार्य किया गया

है। इसी प्रकार, अटल भूजल योजना के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है और ट्रीटेड वेस्ट वाटर का भी अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

इसके अलावा, भू जल स्तर में सुधार के लिए तालाबों का जीर्णोद्धार, फसल विविधीकरण, सूक्ष्म, ग्राउंड वाटर रिचार्ज तथा डीएसआर तकनीक के माध्यम से जल संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने अटल भूजल की टीम को निर्देश दिए कि लक्ष्यों का निर्धारण समयबद्ध ढंग से करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति गुणवत्तापरक की जाए, जिससे हरियाणा का देश में प्रथम स्थान हो सके।



साप्ताहिक सूचना पत्र

भिवानी के नायब तहसीलदार और पटवारी को तुरंत प्रभाव से किया निलंबित

(दिनांक 08.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला भिवानी की एक शिकायतकर्ता द्वारा संपत्ति का इंतकाल देरी से करने तथा गलत कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में भिवानी के नायब तहसीलदार आलमगीर तथा पटवारी ललित कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोनों के विरुद्ध नियम-7 के तहत कार्यवाही भी अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। जिला भिवानी निवासी श्रीमती कमला देवी ने अपने पिता के देहांत के बाद उनकी रजिस्टर्ड वसीयतनामा के अनुसार संपत्ति का इंतकाल उनके व उनकी बहन के नाम किये जाने के संबंध में सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीएम विंडो मुख्यालय द्वारा संबंधित नायब तहसीलदार से रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार आलमगीर ने पटवारी ललित कुमार की

रिपोर्ट का हवाला देते हुए सीएम विंडो पर रिपोर्ट दर्ज की कि उक्त जमीन का इंतकाल करके शिकायतकर्ता को उसकी नकल (कॉपी) की प्रति दे दी गई है, जबकि वास्तव में शिकायतकर्ता अर्थात् श्रीमती कमला देवी को इंतकाल की कोई कॉपी नहीं मिली। सारी कार्यप्रणाली को देखते हुए नायब तहसीलदार और पटवारी को सीएम विंडो पर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दोषी पाया गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नायब तहसीलदार आलमगीर तथा पटवारी ललित कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने तथा नियम-7 के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा वित्त आयुक्त, राजस्व को मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर-अंदर भिजवाना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं।



साप्ताहिक सूचना पत्र

ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 56.36 करोड़ रुपये की 10 नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान

(दिनांक 08.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली 6 जिलों सिरसा, हिसार, पलवल, महेंद्रगढ़, झज्जर और रेवाड़ी में 56.36 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 10 नई परियोजनाएं लागू करने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ग्रामीण संवर्धन जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत जिला हिसार के गांव नियाना, बरवाला में 2.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जल आपूर्ति योजना में सुधार, जिला सिरसा के गाँव कुरंगावाली, कालावाली में 5.89 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जल आपूर्ति योजना का विस्तार और वितरण

प्रणाली को मजबूत करना, 16.88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जिला रेवाड़ी के 7 गांवों में नहर आधारित जलापूर्ति योजना, जिला झज्जर के नियोला ब्लॉक माछरौली में 6.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वतंत्र जल कार्य प्रदान करना, इसके अलावा 2.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जिला व तहसील महेंद्रगढ़ के गांव नांगल सिरोही में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण और पाइप लाइन से जोड़ना, 2.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पलवल के ब्लॉक होडल के गाँव बामनीखेड़ा में जल आपूर्ति योजना में सुधार और पाइप लाइन को बिछाना, एफएचटीसी, 2 ट्यूबवेल को लगाना और 2 अंडरग्राउंड टैंक का निर्माण करना शामिल है।



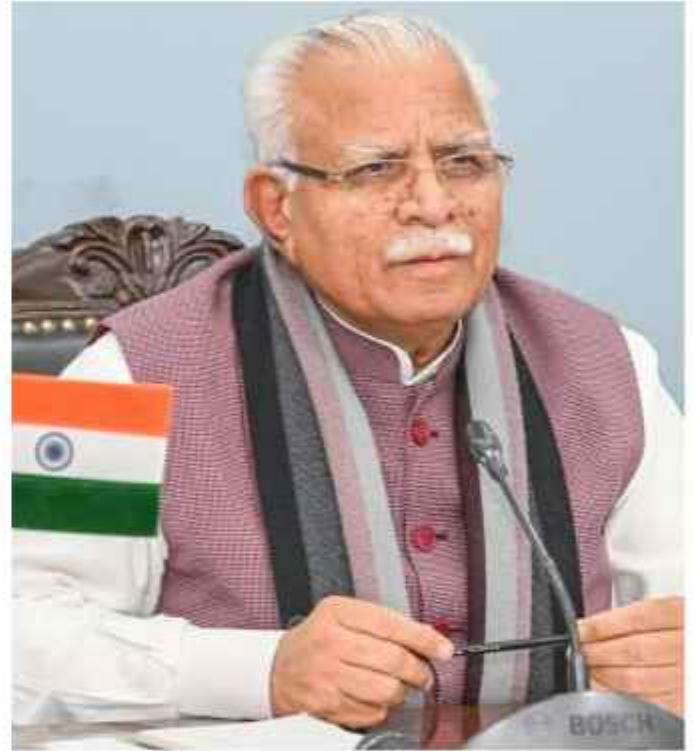
साप्ताहिक सूचना पत्र

पंचकूला में परिवार पहचान पत्र को लेकर आयोजित एक वर्कशॉप को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करना

(दिनांक 08.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज पंचकूला में परिवार पहचान पत्र को लेकर आयोजित एक वर्कशॉप को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित कर कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के डाटा का सफल विश्लेषण करने के बाद हम एक बेहतरीन परियोजना दुनिया के सामने रख सकेंगे। दुनिया भर में परिवार पहचान पत्र जैसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हरियाणा की इस अनूठी परियोजना का अध्ययन करने के लिए कहा है जिसके बाद कई राज्यों ने अपनी टीम हरियाणा में भेजी हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पात्र लोगों को सभी तरह की सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ देने की



अवधारणा को साकार करने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र परियोजना शुरू की गई थी। हालांकि पहले नागरिकता की पहचान के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था थी, लेकिन समाज में परिवार, जिसमें बच्चे से लेकर वृद्धजन होते हैं, के



साप्ताहिक सूचना पत्र

डाटा की सटीक जानकारी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं थी।

उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के डाटा अनुसार ही प्रदेश में बहुत से कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही थी। हमने अधिकारियों के सहयोग से परिवार पहचान पत्र को शुरू किया है जिसके बेहतरीन नतीजे सामने आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से परिवार पहचान पत्र के प्रति लोगों का संतुष्टि स्तर और अधिक बढ़ाने का आह्वान करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र के आने से पहले अपात्र लोग भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा लेते थे और पात्र लोग वंचित रह जाते थे।

आज सरकार के पास परिवार की सही जानकारी होने से पात्र लोगों को सभी योजनाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है जिसमें ओल्ड एज पेंशन, बीपील कार्ड सहित अन्य कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र

को लेकर आय सम्बन्धी त्रुटियों को सही करते समय अधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि लोगों में किसी प्रकार की निराशा न हो और परिवार पहचान पत्र के प्रति जनता में विश्वास और मजबूत हो। साथ ही इस परियोजना की सफलता के लिए लोगों से मिलने वाले बेहतरीन सुझावों को भी शामिल करने की दिशा में भी कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार को खुशहाल बनाने में परिवार पहचान पत्र परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।

इस अवसर पर परिवार पहचान पत्र को लेकर आयोजित वर्कशॉप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री वी उमाशंकर जी ने बताया कि आज 11 जिलों की यह वर्कशॉप आयोजित की गई है जिसमें विभिन्न सत्रों में अधिकारियों से अच्छे सुझाव आये हैं।

उन्होंने वर्कशॉप में आयोजित सत्रों को लेकर भी जानकारी दी।



साप्ताहिक सूचना पत्र

नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिट में शिरकत करना

(दिनांक 09.02.2024)



प्रभाव :- माननीय मुख्यमंत्री जी आज नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल बिजनेस समिट में कहा कि प्रदेश की लाभप्रद भौगोलिक स्थिति, प्रगतिशील नीतियों और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण आज हरियाणा वैश्विक निवेशकों के लिए

शीर्ष पसंद बन गया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश की लगातार बेहतरीन रैंकिंग और लोकेशन एडवांटेज के चलते जापानी सहित अन्य मल्टीनेशनल कंपनियाँ हरियाणा में निवेश करने के लिए लगातार रुचि दिखा रही हैं।



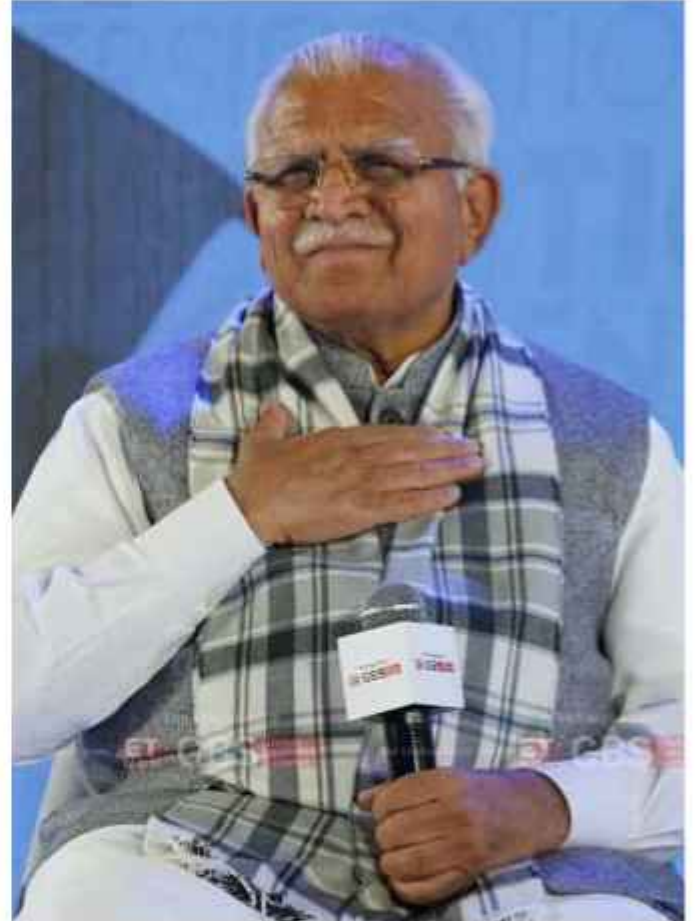
साप्ताहिक सूचना पत्र

उन्होंने कहा कि 500 फॉर्चून कंपनी में से 400 कंपनी के ऑफिस गुरुग्राम में पहले से ही स्थापित है।

50 बड़ी जापानी कंपनियों के साथ हाल ही में हमने अपने रिलेशंस बढ़ाने के लिए एक सफल सेमिनार भी आयोजित किया है।

गुरुग्राम के आसपास का फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत सहित अन्य एनसीआर एरिया आज इन्वेस्टमेंट के लिए प्रीफर्ड डेस्टिनेशन अर्थात् पहली पसंद बन चुका है।

हरियाणा को विकासोन्मुख प्रदेश बताते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की आबादी देश की आबादी का मात्र 2 प्रतिशत और एरिया 1.3 प्रतिशत है, फिर भी आज जीएसडीपी में प्रदेश का योगदान 3.69 प्रतिशत है। आने वाले 4-5 वर्षों में यह आंकड़ा 4 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमारा



अपॉइंटमेंट बढ़ रहा है और हमारे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है। जीएसटी कलेक्शन में बड़े राज्यों में आज हरियाणा राज्य नंबर एक पायदान पर आया है। उन्होंने कहा कि किसानों की चिंताओं को खत्म करने के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' सहित अन्य कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।



साप्ताहिक सूचना पत्र

नई दिल्ली में मीडियों कर्मियों से बार्ता

(दिनांक 09.02.2024)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई दिल्ली में मीडियों कर्मियों से बात कर कहा कि आज उनके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि देश की जनता को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉ एम. एस. स्वामी नाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस निर्णय का स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जताया है। उन्होंने कहा

कि देश के लिए अतुलनीय योगदान देने वाले तीनों महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करना प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव और सम्मान की बात है।

उन्होंने इन तीनों विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करने पर देश के कृषक, किसानबंधु, कृषि वैज्ञानिक और देश की धारा में लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं का पालन करने वाले जनमानस को बधाई व शुभकामनाएं दी।

आगामी 20 फरवरी से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि "विपक्ष के इस ब्यान को उन्होंने पढ़ा है लेकिन इससे पहले भी वे (विपक्ष) अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो उन्होंने विपक्ष को चुनौती दी थी कि जब भी



साप्ताहिक सूचना पत्र

कोई सत्र आए तो वे जरूर अविश्वास प्रस्ताव लाए ताकि हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को वे सुन सकें अन्यथा वे किसी भी सत्र में केवल बोलते हैं सुनते नहीं हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि “हो सकता है हमारे कार्यों को सुनने के बाद उनमें से किसी का पाला बदलने का मन बदल जाएं, हम उसके लिए भी तैयार हैं”।

आगामी 16 फरवरी को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रेवाड़ी में एम्स के शिलान्यास के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि रेवाड़ी एम्स की योजना बहुत वर्षों से भूमि और वन विभाग की स्वीकृतियों के कारण से अधर में लटकी हुई थी लेकिन अब रेवाड़ी एम्स की स्थापना को लेकर रास्ते साफ हो गए हैं तथा एम्स की स्थापना को लेकर वन विभाग से स्वीकृतियां और पंचायत द्वारा भूमि दिए जाने के उपरांत टेंडर कर दिये गये हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी 16 फरवरी को एम्स के साथ अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी करेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की जानकारी केन्द्र सरकार को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि इसी दिन ‘विकसित भारत-विकसित हरियाणा’ की थीम से माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। इस संबंध में हमारे द्वारा योजना बनाई जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण प्रदेशवासी ऑनलाइन सुन सकें।

लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी यदि कोई पार्टी कर रही है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकसभा कार्यालय एक साथ खोले हैं और इस संबंध में हमारी सभी आन्तरिक तैयारियां हो चुकी हैं।



साप्ताहिक सूचना पत्र

श्री राम मंदिर अयोध्या की चंदन की खुशबू से सुगंधित डाक टिकट की सराहना करना

(दिनांक 09.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कर्नल एसएफएच रिजवी ने श्री राम मन्दिर, अयोध्या की चन्दन की खुशबू से सुगंधित एवं गोल्ड फॉयल प्रिंटेड डाक टिकट भेंट की। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 18.01.2024 को अयोध्या में इस डाक टिकट को जारी किया गया था।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाक टिकट को बेहद खूबसूरत बताते हुए इसकी प्रशंसा की। राम मंदिर भारतीय सनातन संस्कृति की आस्था का केंद्र बिंदु है जो समस्त समाज को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रभु श्री राम मंदिर पर आधारित ये डाक टिकट आम जनमानस और आने वाली पीढ़ियों को हमारी संस्कृति की जड़ों तक फिर से जोड़ने का कार्य करेगी।

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कर्नल



एसएफएच रिजवी ने बताया की श्री राम मन्दिर जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर डाक विभाग द्वारा डाक टिकटों का सेट तैयार किया गया है। इन डाक टिकटों के मुद्रण की प्रक्रिया में श्री राम जन्मभूमि के जल एवं मिट्टी का प्रयोग किया गया है जो कि श्री राम के चौतन्य भाव और आशीर्वाद से युक्त है। यह डाक टिकट चन्दन की खुशबू से सुगंधित है। डाक टिकटों को दिव्य प्रकाश से प्रदीप्त करने के लिए इस मिनिएचर शीट के कुछ हिस्सों पर गोल्ड फॉयल प्रिंटिंग की गई है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

190 करोड़ रुपये से अधिक की 33 नई
परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करना

(दिनांक 09.02.2024)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना के

तहत 5 जिलों नामतरु जींद, हिसार, सिरसा, कैथल और भिवानी में 190 करोड़ रुपये करोड़ रुपये से अधिक लागत की 33 नई परियोजनाएं लागू



साप्ताहिक सूचना पत्र

करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि महाग्राम योजना के तहत जिला जींद के गांव नगुरां में जल आपूर्ति प्रणाली का संवर्धन और जल कार्यों के निर्माण के लिए 43.91 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से व 25.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध करवाना और जिला हिसार के खेदड़ में जल आपूर्ति योजना के उन्नयन के लिए 10.63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के नए कार्य शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि सिरसा जिले में ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत विभिन्न गांव में परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई जिला सिरसा के तहत गांव मौजगढ़ में 2.38 करोड़ रुपये, ग्राम पाना के लिए 2.88 करोड़ रुपये, ग्राम सुबेवाला खेड़ा के लिए 2.29 करोड़ रुपये, गांव डिंग और मोचीवाली के लिए 4.71 करोड़ रुपये, ग्राम फेरवाई के लिए 5.83 करोड़ रुपये, गांव गुसाईयाना के

लिए 3.78 करोड़ रुपये, कोटली और केशुपुरा दोनों गांवों के लिए 10.84 करोड़ रुपये तथा ग्राम ममड़ व खेड़ा सैनपाल और नथोर के लिए 5.91 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्माण कार्य करवाना शामिल हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि हिसार जिले में ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में गांव ढाणी मेहंदा के लिए 3 करोड़ रुपये, ग्राम धानी पुरिया के लिए 5.71 करोड़ रुपये, ग्राम गढ़ी के लिए 3.13 करोड़ रुपये, गांव हजमपुर के लिए 2.57 करोड़ रुपये, ग्राम प्रेम नगर के लिए 4.24 करोड़ रुपये तथा गांव नंगथला में 4.21 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत जलापूर्ति तथा अन्य सुधार निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। प्रवक्ता ने जिला भिवानी में स्वीकृत परियोजना में तोशाम तहसील के गांव दुल्हेड़ी से रिवासा रोड तक 12.19 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाना शामिल है।



साप्ताहिक सूचना पत्र

यमुनानगर जिले मे 24.02 करोड रुपए से अधिक लागत की 16 ओडीआर सड़कों के सुधार को स्वीकृति' प्रदान

(दिनांक 09.02.2024)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुनानगर जिले में 16 ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रोजेक्ट पर 24.02 करोड रुपये से ज्यादा की लागत आएगी। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को बाजार केंद्रों, तहसील मुख्यालयों, ब्लॉक विकास मुख्यालयों, रेलवे स्टेशनों आदि तक पहुंच प्रदान करेंगी। इन सड़कों को अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) के नाम में जाना जाता है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक अधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इस परियोजना के तहत विशेष मरम्मत में यमुनानगर जिले में 0.360 किलोमीटर तक फैले गांव कैथ कलानौर से फतेहपुर तक का चौड़ीकरण और

सुदृढीकरण किया जाएगा।

इसी प्रकार गांव बड़ी माजरा से एच.बी. तीर्थ नगर तक की अनुमानित लागत 29.91 लाख रुपए, ग्राम कैथ कलानौर रोड से इस्सरपुर तक अनुमानित लागत 64.11 लाख रुपए, यमुनानगर जिले में ग्राम शादीपुर जयपुर से पंजुपुर रोड की अनुमानित लागत 14.11 लाख रुपए, ग्राम पंसारा सहजादपुर रोड से एच.बी. साबेपुर की लागत 27.16 लाख रुपए, गांव पंसारा शहजादपुर रोड से मेहर माजरा तक की अनुमानित लागत 34.19 लाख रुपए, ग्राम बुरिया खदरी देवधर से ग्राम फतेहगढ़ तक सड़क की अनुमानित लागत 46.64 लाख रुपए, गांव बधी माजरा से गधौली माजरी तक सड़क की अनुमानित लागत 29.29 लाख रुपए, गांव जगाधरी छछरौली पोंटा रोड से बलाचौर रोड की



साप्ताहिक सूचना पत्र



अनुमानित लागत 51.20 लाख रुपए तथा ग्राम कैथ कलानौर से परवालो सड़क पर अनुमानित लागत 31.77 लाख रुपए आएगी। इसके अलावा, यमुनानगर जिले में रामपुर तक पंसारा शहजादपुर सड़क की अनुमानित लागत 67.41 लाख रुपए, पंसारा शहजादपुर से कनालसी तक 13.48 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ तथा

यमुनानगर जिले में बड़ी माजरा से होते हुए एसबीआई पांसारा रोड 42.62 लाख रुपए लागत आएगी। इसी प्रकार यमुनानगर जिले में ग्राम बुडिया खदरी देवधर रोड के साथ-साथ ग्राम बुडिया खदरी देवधर रोड, जगाधरी बुडिया देवधर रोड तथा देवधर नैनावली रोड के सुदृढीकरण पर अनुमानित 18.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी।



साप्ताहिक सूचना पत्र

भारत रत्न से सम्मानित लाल कृष्ण आडवाणी से की मुलाकात

(दिनांक 10.02.2024)



प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न मिलने पर बधाई दी।

इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री आडवाणी को हरियाणा में चलाई जा रही योजनाओं व कार्यों की जानकारी देते हुए नौ सालों की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक भी भेंट की। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने हरियाणा में किये जा रहे कार्यों पर प्रसन्नता जताई।



साप्ताहिक सूचना पत्र

मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि श्री लालकृष्ण आडवाणी हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते रहे हैं।

उनसे मिलने में विशेष स्नेह की अनुभूति होती है। उन्हें 3 फरवरी को जब भारत रत्न देने की घोषणा हुई, हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है। मैंने तभी फैसला किया था कि जब दिल्ली आना होगा तो मुलाकात जरूर करेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे भारत रत्न दिए जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं। वे श्री अडवानी की लंबी आयु की कामना भी करते हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत रत्न देश के प्रति संबंधित व्यक्ति के योगदान को देखकर दिया जाता है। प्रतिभा खोज में जातियां नहीं, बल्कि काम देखा जाता है। चाहे जाति कोई भी हो, उल्लेखनीय कार्य के आधार पर

ही चयनित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाति की विचारधारा में कभी बंधे हों। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स देश में कभी भी नहीं होनी चाहिए, यह तो हानिकारक है। जो लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की सोचते हैं, वे अच्छा नहीं कर सकते।

केंद्रीय गृहमंत्री जी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि खासकर किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली कूच को लेकर सभी व्यवस्थाएं ठीक रहे, शांति बनी रहे, इस प्रकार की सारी बातें हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि दिल्ली हरियाणा का लगभग केंद्र है।

हरियाणा के कार्यों के लिए दिल्ली आते रहते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे नेताओं व गणमान्य लोगों से यहां मुलाकातें होती हैं। समसामयिक विषयों पर चर्चा होती है और राजनैतिक लोगों से भी मुलाकातें होती रहती हैं।

